

Indian Air Force Outreach and Air Display (Jaipur).



Jaipur In a special outreach programme, Surya Kiran Aerobatic Team and Sarang Helicopter Display Team engaged youth of Jaipur at the Bhagwat Singh Mehta Auditorium of Harishchandra Mathur Rajasthan Institute of Public Administration (HCM RIPA). During the initial encounter, the teams addressed the reasons why discipline, teamwork, and dedication create professional excellence in the Indian Air Force, and the focus on career opportunities and the intensity of training. Students on NCC, school students and hearing-impaired students who attended the event were excited after the encounter with the Indian Air Force ambassadors. The teams were also able to give information about the forthcoming air show which was to be held at Jal Mahal on 20 and 22 February, and also on the practice flights which led to the major display.

Key Highlights

- Meeting was at the Bhagwat Singh Mehta Auditorium of HCM RIPA, Jaipur.
- There were participants (NCC cadets, school students and hearing-impaired students).
- Areas of focus include; national service, discipline, excellence, teamwork and commitment.
- Jal Mahal Air show on 20 and 22 February with practice display before the actual show.

Surya Kiran Aerobatic Team is recognized for promoting aerobatic displays on the ground and in the air to the audience.

Profile and Capabilities

- Established in 1996.
- Asia has the only nine planes aerobat team; one of the few in the world.
- Flies Hawk Mk-132 jets red and white.
- The loops, barrel rolls, inverted flight and the trendy DNA formation are also signature manoeuvres.

The first two stages involved in the performance management process are the track record and team composition.

- Presentation of more than 800 exhibitions also in China, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Singapore, and the UAE.
- Team has 14 pilots.
- Group Captain Ajay Dasrathi (experienced in Su-30 MKI) is the leader of the group.
- Wing Commander Tejeshwar Singh is the Deputy Leader.
- Jaipur has three pilots: Wing Commander Rajesh Kajla, Wing Commander Ankit Vashishth and Squadron Leader Sanjesh Singh.

Indigenous Technology Push

- Indigenous smoke pods now have been implemented.
- Developed at the Repair Workshop of 11 Base of the Indian air force, Nashik.
- Enables smoke effects on displaying in tricolour in the spirit of the Aatmanirbhar Bharat.

Sarang Helicopter Display Team:-

Profile and Achievements

- World renowned in colourful helicopters and accurate formation flying.
- First world performance: 2004, in Singapore, the Asian Aerospace Show.
- Performed in over 390 places and had over 1200 displays.

Dhruv Helicopter

- It runs the Dhruv helicopter that was developed and designed by Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
- Characterized as a multi-role helicopter and an all-weather aircraft, and a powerful icon of self-reliance.
- On 22 February day, following practice flights to 20 February, a display of 5 helicopters will be demonstrated over Jal Mahal.

Exam Relevance for RAS/UPSC

- The preparedness of defence and soft-power outreach by means of public engagement.
- Aatmanirbhar Bharat and indigenous defence by locally made smoke pods and HAL platforms.
- Disciplined training, teamwork and institutional excellence in uniformed services.
- Inclusion and inspiration activities that involve hearing impaired students in the public programs.

Conclusion

The Jaipur engagement of Surya Kiran Aerobatic Team and the Sarang Helicopter Display Team was an amalgamation of inspiration and pragmatic opinion of the Air Force professionalism and training and national service. The programme had linked the youthful dream to the Indian Air Force precision, discipline, and capability of the natives, with a big air show planned at Jal Mahal, on 20 and 22 February, making the skies of the city a demonstration of talent and self-sufficiency.

MCQs (RAS Prelims)

MCQ 1: The Surya Kiran Aerobatic Team can be defined as:

- (a) A group of 9 airplane aerobic team that was formed in 1996.
- (b) Helicopter display team which also uses Dhruv helicopters.
- (c) A training unit that was developed in 2004 to conduct international air shows.
- (d) A two plane demonstration squad on Su-30 MKI exclusively.

Answer: (a)

Explanation : Surya Kiran Aerobatic Team, which was founded in 1996, is said to be the only nine-member aerobatic troop in Asia. It does aerobatics on Hawk Mk-132 jet planes and is not to be confused with the Sarang team, a helicopter display team that uses the Dhruv platform.

MCQ 2: What platform the Sarang Helicopter Display Team uses to put on formation displays?

- (a) Hawk Mk-132
- (b) Dhruv helicopter
- (c) Su-30 MKI

(d) Mirage 2000

Answer: (b)

Explanation: Sarang Helicopter Display Team uses the Dhruv helicopter, which is an aircraft designed and developed by Hindustan aeronautic Limited (HAL). Surya Kiran uses Hawk Mk-132 and Su-30 MKI is mentioned as the aircraft used by the team leader of the Surya Kiran team in his experience profile.

MCQ 3: The new incorporation of aboriginal smoke pod that is correlated to Surya Kiran allows:

- (a) Long distance air-to-air refuelling at displays.
- (b) Tricolour smoke effects of aerobatic performances.
- (c) Transformation of jets into aerial unmanned vehicles.
- (d) Operation of landing in the night on water bodies.

Answer: (b)

Explanation: Indigenous smoke pods were fitted into the planes, to give the aircraft a fascinating tricolour appearance in the sky during performances. These smoke pods were invented in 11 Base Repair Depot in Nashik of the Indian Air Force and were connected with the wider focus on self-reliance (Aatmanirbhar Bharat).

भारतीय वायुसेना का जनसंपर्क एवं वायु प्रदर्शन (जयपुर)

जयपुर में एक विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने युवाओं से संवाद किया। यह कार्यक्रम हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित हुआ। संवाद के दौरान टीमों ने समझाया कि अनुशासन, टीमवर्क और समर्पण कैसे भारतीय वायुसेना में पेशेवर उत्कृष्टता का आधार बनते हैं। साथ ही वायुसेना में करियर के अवसरों और कठोर प्रशिक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र-छात्राएं तथा मूक-बधिर विद्यार्थी शामिल रहे, जो वायुसेना के एम्बेसडर्स से मिलकर उत्साहित दिखे। टीमों ने जलमहल पर 20 और 22 फरवरी को प्रस्तावित एयर शो तथा मुख्य प्रदर्शन से पहले होने वाली अभ्यास उड़ानों के बारे में भी जानकारी साझा की।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम स्थल: एचसीएम रीपा, जयपुर का भगवत सिंह मेहता सभागार।
- प्रतिभागी: एनसीसी कैडेट्स, स्कूली छात्र-छात्राएं और मूक-बधिर विद्यार्थी।

- मुख्य संदेश: राष्ट्र सेवा, अनुशासन, उत्कृष्टता, टीमवर्क और प्रतिबद्धता।
- जलमहल एयर शो: 20 और 22 फरवरी; मुख्य प्रदर्शन से पहले अभ्यास उड़ानें।

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम

सूर्य किरण एरोबैटिक टीम दर्शकों के सामने जमीन और आकाश दोनों स्तरों पर एरोबैटिक प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है।

प्रोफ़ाइल एवं क्षमताएँ

- स्थापना: 1996।
- एशिया की एकमात्र नौ-विमान एरोबैटिक टीम; विश्व की चुनिंदा टीमों में शामिल।
- लाल-सफेद रंग के हॉक एमके-132 जेट विमानों पर उड़ान।
- प्रमुख करतब: लूप, बैरल रोल, उलटी उड़ान तथा लोकप्रिय “डीएनए” संरचना।

प्रदर्शन रिकॉर्ड एवं टीम संरचना

- 800 से अधिक प्रदर्शन; चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में।
- टीम में 14 पायलट।
- टीम लीडर: ग्रुप कैप्टन अजय दसरथी (सु-30 एमकेआई के अनुभवी पायलट)।
- डिप्टी लीडर: विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह।
- जयपुर से जुड़े तीन पायलट:
 - विंग कमांडर राजेश काजला
 - विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ
 - स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह

स्वदेशी तकनीक पर जोर

- स्वदेशी स्मोक पॉइंस का हाल ही में एकीकरण।
- भारतीय वायुसेना के 11 बेस रिपेयर डिपो, नासिक में विकसित।
- प्रदर्शन के दौरान आकाश में तिरंगे के रंगों वाली धुएँ की छटा संभव; आत्मनिर्भर भारत की भावना से जुड़ा पहलू।

सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम

प्रोफ़ाइल एवं उपलब्धियाँ

- रंग-बिरंगे हेलीकॉप्टरों और सटीक गठन उड़ान के लिए विश्व प्रसिद्ध।
- पहली अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुति: 2004, सिंगापुर के एशियन एयरोस्पेस शो में।

- 390 से अधिक स्थानों पर 1200 से अधिक प्रदर्शन।

प्लेटफॉर्म: ध्रुव हेलीकॉप्टर

- ध्रुव हेलीकॉप्टर का संचालन, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने डिज़ाइन और विकसित किया है।
- सर्व-मौसम और बहु-उद्देश्यीय क्षमता; आत्मनिर्भरता का मजबूत प्रतीक।
- 20 फरवरी तक अभ्यास उड़ानों के बाद 22 फरवरी को जलमहल के ऊपर 5 हेलीकॉप्टरों का सामूहिक प्रदर्शन प्रस्तावित।

आरएएस/यूपीएससी परीक्षा हेतु प्रासंगिकता

- रक्षा तैयारी के साथ जनसंपर्क के माध्यम से “सॉफ्ट पावर” पहल।
- आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा क्षमता: स्वदेशी स्मोक पॉइंस तथा एचएएल के प्लेटफॉर्म।
- अनुशासित प्रशिक्षण, टीमवर्क और संस्थागत उत्कृष्टता का महत्व।
- मूक-बधिर विद्यार्थियों की भागीदारी के माध्यम से समावेशन और प्रेरणा-आधारित पहल।

निष्कर्ष

जयपुर में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का संवाद कार्यक्रम प्रेरणा के साथ-साथ भारतीय वायुसेना की पेशेवर दक्षता, प्रशिक्षण संस्कृति और राष्ट्र सेवा के दृष्टिकोण की व्यावहारिक झलक लेकर आया। 20 और 22 फरवरी को जलमहल पर प्रस्तावित एयर शो के साथ यह पहल युवाओं की आकांक्षाओं को वायुसेना की सटीकता, अनुशासन और स्वदेशी क्षमता से जोड़ती है, जिससे शहर का आकाश कौशल और आत्मनिर्भरता के प्रदर्शन का मंच बनेगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारंभिक परीक्षा)

बहुविकल्पीय प्रश्न 1: सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के बारे में सही कथन कौन-सा है?

- (a) 1996 में स्थापित नौ-विमान एरोबैटिक टीम
- (b) ध्रुव हेलीकॉप्टरों का संचालन करने वाली हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम
- (c) 2004 में अंतरराष्ट्रीय एयर शो हेतु गठित प्रशिक्षण इकाई
- (d) केवल सु-30 एमकेआई पर आधारित दो-विमान प्रदर्शन दस्ता

उत्तर: (a)

व्याख्या: सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 1996 में स्थापित हुई और इसे एशिया की एकमात्र नौ-विमान एरोबैटिक टीम बताया गया है। यह हॉक एमके-132 जेट विमानों पर एरोबैटिक्स का प्रदर्शन करती है। इसे सारंग टीम से अलग समझना आवश्यक है, क्योंकि सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ध्रुव हेलीकॉप्टर के माध्यम से गठन उड़ान का प्रदर्शन करती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न 2: सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम गठन उड़ान प्रदर्शन के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है?

- (a) हॉक एमके-132

- (b) ध्रुव हेलीकॉप्टर
(c) सु-30 एमकेआई
(d) मिराज 2000

उत्तर: (b)

व्याख्या: सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ध्रुव हेलीकॉप्टर का संचालन करती है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने डिज़ाइन और विकसित किया है। सूर्य किरण टीम हॉक एमके-132 पर प्रदर्शन करती है, जबकि सु-30 एमकेआई का संदर्भ सूर्य किरण टीम लीडर के अनुभव से जुड़ा है, न कि सारंग टीम के प्लेटफॉर्म से।

बहुविकल्पीय प्रश्न 3: सूर्य किरण टीम के विमानों में स्वदेशी स्मोक पॉइस के एकीकरण से क्या संभव हुआ?

- (a) प्रदर्शन के दौरान लंबी दूरी तक हवा में ईंधन भरना
(b) एरोबैटिक प्रदर्शन में तिरंगे रंगों वाली धुएँ की छटा
(c) जेट विमानों को मानवरहित प्लेटफॉर्म में बदलना
(d) जल निकायों पर रात में विशेष लैंडिंग संचालन

उत्तर: (b)

व्याख्या: स्वदेशी स्मोक पॉइस को विमानों में जोड़ने से प्रदर्शन के दौरान आकाश में तिरंगे के रंगों वाली आकर्षक धुएँ की छटा बनाई जा सकती है। यह विकास भारतीय वायुसेना के 11 बेस रिपेयर डिपो, नासिक में किया गया है और इसे आत्मनिर्भर भारत की व्यापक भावना से जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें स्वदेशी तकनीकी क्षमता का उपयोग होता है।

To provide youths of Rajasthan with the budget of the Youth Affairs and Sports.



Youth Affairs and Sports Minister of Rajasthan Colonel Rajyavardhan Rathore addressed the State Assembly saying that the government of Chief Minister Bhajanlal Sharma is determined to see to it that the youth are developed in all aspects. He associated this agenda with the government employment, increased opportunities in the business sector and assisting sports talents nationally and internationally. In the Assembly debate on Demand No. 26, the department grant demands were voted by the House by voice in the Demand. The minister also put forward a comparative narrative of the five-year performances of the last government compared to the two-year performance of the present government in terms of awarding the athletes, appointing of athletes out of turn, acquiring sports equipments, hosting of a major sports event and other welfare activities like providing of life and accident insurance to the athletes.

Major Resolutions at the Assembly.

- Youth Affairs and Sports Department grants Demand No. 26 were discussed by the Assembly.
- Grant demands of 2,298, 528, 000 (229.8528 crore) were approved by voice vote.
- The minister emphasized that it is the central role of the government to provide youth with more opportunities.

Athlete Assistance and Targets

- The old regime has given 72 crore in the form of incentive support to five-year-old and above athletes.
- ₹40 crore was given by the current government in two years, and an interest in increasing this support to ₹100 crore was announced.

Out-of-Turn Appointments of Sportspersons.

- In five years, the former regime had done 248 out-of-turn appointments.
- In two years the government of at the time conducted an 186 out-of-turn process.
- According to the minister, the overall figure will go beyond 300 by June 2026.

Sports Equipment and Readiness to Practice.

- The last government had purchased sports equipments at a cost of 6.49 crore (also 6.50 crore) in five years.
- The current government wrote that within two years, it has purchased equipment to the tune of 18 crores and has also reported to have purchased approximately 19 crores.
- The minister associated the bigger equipment availability with the better and more frequent practicing by the athletes.

Awards and Major Sporting Events.

- New awards **Maharana Pratap Awards and Guru Vashishth Awards** are likely to be awarded very soon; a list has been made accordingly.
- The minister claimed that the last government never gave these awards once in its term.
- He further stated that there was no event conducted at the national level during the rule of the previous government but instead the current government organized the Khelo India University Games 2025 according to the standards of central government.
- The state incurred 100 crores expenses on the event hosting.
- There were over 7,000 participants and the athletes of Rajasthan were able to win 34 medals.

Performance Results and Global acknowledgment.

- Rajasthan won 60 medals in the Khelo India Youth Games in third position.

At the Paris Para Olympics 2024:

- Avani Lekhara won gold.
- Sundar Singh Gurjar was the bronze winner.
- Mona Agarwal won bronze.
- Minister also said that the Rajasthan sportsmen had managed a fourth place finish in the Paris Olympics and it is a big deal.

A Life Insurance Scheme for Sportspeople.

- Sports under the Sports Life Insurance Scheme are getting covered by accident and life insurance to a maximum of 25 lakh.
- The mentioned purpose is to minimize the uncertainties in the future and offer risk coverage.

Conclusion

The passing of Demand No. 26 by the Assembly and the review of the performance of the minister indicate that the policy of incentives to the athletes, accelerated out-of-turn appointments, and sport infrastructure through the purchase of the equipment and state awards is a priority. The organization of a big national event and the extension of insurance coverage is presented as the actions aimed to facilitate the development of the sports infrastructure in Rajasthan and minimize insecurity among athletes, and the government presents these initiatives as the steps of a more general youth development strategy.

MCQs (RAS Prelims)

MCQ 1: The grants which were granted by voice vote in the Assembly of Rajasthan in the discussion of Youth Affairs and Sports (Demand No. 26) were:

- (a) ₹2,298,528,000
- (b) ₹1,000,000,000
- (c) ₹7,200,000,000
- (d) ₹229,852,800,000

Answer: (a)

Explanation: The voice-vote grant demands were 2298528000,000 that is equivalent to 229.8528 crore. The remaining characters either lose the zeros or portray irrelevant figures of the debate.

MCQ 2: Which of the following pairs is well matched as indicated in the Assembly briefing?

- (a) Government out-of-turn appointments (5 years old): 186, Current government (2 years): 248
- (b) Past government athlete support (5 years): 40 crore; present day government (2 years): 72 crore.
- (c) Government past out-of-turn appointments (5 years): 248; Current government (2 years): 186
- (d) Khelo India University Games 2025 were hosted in a previous government; 2025 none in current government.

Answer: (c)

Explanation: This was compared to 248 out-of-turn appointments in five years under the previous government against 186 in two years under the current government. The other alternatives are reversed or in opposition to the event-hosting announcement.

MCQ 3: In what case, according to the minister, are the statements regarding the result of sports and welfare measures accurate?

- (a) Rajasthan has won 34 medals during Khelo India Youth Games and has come up with 10 lakh insurance cover.
- (b) Rajasthan achieved third in the Khelo India Youth Games with 60 medals and offers insurance cover to 25 lakh.

(c) The 2024 Khelo India University Games held in Rajasthan with 3,400 participating athletes have ₹50 lakh insurance cover.

(d) Rajasthan has 60 medals in Khelo India University Games 2025 and offers insurance cover to coaches only.

Answer: (b)

Explanation: According to the minister, Rajasthan had won 60 states in Khelo India Youth Games and that Sports Life Insurance Scheme will cover accident and life insurance up to 25 lakh. The other alternatives confuse the events, figures, and the coverage limits.

राजस्थान के युवाओं के लिए युवा मामले एवं खेल विभाग के बजट प्रावधानों के माध्यम से सहायता और अवसर बढ़ाना

राजस्थान के युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस एजेंडे को सरकारी रोजगार, निजी क्षेत्र में अवसरों के विस्तार तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को समर्थन देने से जोड़ा। मांग संख्या 26 पर हुई बहस के दौरान सदन ने विभाग की अनुदान मांगों ध्वनिमत से पारित कीं। मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार के पाँच वर्षों के कार्य और वर्तमान सरकार के दो वर्षों के कार्य का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन सहायता, क्रम से हटकर नियुक्तियाँ, खेल उपकरणों की खरीद, बड़े खेल आयोजन की मेजबानी तथा खिलाड़ियों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा जैसे कल्याणकारी कदम शामिल रहे।

विधानसभा में प्रमुख निर्णय

- विधानसभा में युवा मामले एवं खेल विभाग की अनुदान मांगों (मांग संख्या 26) पर चर्चा हुई।
- कुल अनुदान मांगें ₹2,298,528,000 (₹229.8528 करोड़) ध्वनिमत से स्वीकृत हुईं।
- मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराना सरकार की केंद्रीय भूमिका है।

खिलाड़ियों के लिए सहायता और लक्ष्य

- पूर्ववर्ती सरकार ने पाँच वर्षों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में ₹72 करोड़ की सहायता दी।
- वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में ₹40 करोड़ की सहायता दी और इसे ₹100 करोड़ तक बढ़ाने की मंशा बताई।

खिलाड़ियों की क्रम से हटकर नियुक्तियाँ

- पूर्ववर्ती सरकार ने पाँच वर्षों में 248 क्रम से हटकर नियुक्तियाँ कीं।
- वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में 186 क्रम से हटकर नियुक्तियाँ कीं।

- मंत्री के अनुसार, जून 2026 तक यह संख्या 300 से अधिक हो जाएगी।

खेल उपकरण और अभ्यास की तैयारी

- पूर्ववर्ती सरकार ने पाँच वर्षों में ₹6.49 करोड़ (कहीं ₹6.50 करोड़) के खेल उपकरण खरीदे।
- वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में ₹18 करोड़ के उपकरण खरीदने की बात कही और यह भी बताया कि खरीद लगभग ₹19 करोड़ तक पहुँच चुकी है।
- मंत्री ने अधिक उपकरण उपलब्धता को खिलाड़ियों के बेहतर और अधिक नियमित अभ्यास से जोड़ा।

पुरस्कार और बड़े खेल आयोजन

- महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार शीघ्र दिए जाने की बात कही गई; सूची तैयार होने की जानकारी दी गई।
- मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल में ये पुरस्कार एक बार भी नहीं दिए।
- उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन नहीं हुआ, जबकि वर्तमान सरकार ने केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार “खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल-2025” का आयोजन किया।
- आयोजन पर राज्य ने ₹100 करोड़ व्यय किए।
- 7,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और राजस्थान के खिलाड़ियों ने 34 पदक जीते।

प्रदर्शन परिणाम और वैश्विक पहचान

- “खेलो इंडिया युवा खेल” में राजस्थान ने 60 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- पेरिस पैरा ओलंपिक-2024 में:
 - अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता।
 - सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता।
 - मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता।
- मंत्री ने कहा कि पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के खिलाड़ी चौथे स्थान पर भी रहे, जिसे उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया।

खिलाड़ियों के लिए जीवन बीमा योजना

- “खेल जीवन बीमा योजना” के तहत खिलाड़ियों को अधिकतम ₹25 लाख तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जा रहा है।
- उद्देश्य भविष्य की अनिश्चितताओं को कम करना और जोखिम सुरक्षा प्रदान करना बताया गया।

निष्कर्ष

विधानसभा द्वारा मांग संख्या 26 का पारित होना और मंत्री द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक समीक्षा यह संकेत देती है कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन, क्रम से हटकर नियुक्तियों की गति, उपकरण खरीद के जरिए खेल अवसंरचना का सुदृढीकरण और राज्य स्तरीय पुरस्कारों के माध्यम से सम्मान को प्राथमिकता दी जा रही है। बड़े राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी और बीमा कवरेज के विस्तार को राजस्थान में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने तथा खिलाड़ियों की असुरक्षा घटाने की दिशा में कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और सरकार इन्हें व्यापक युवा विकास रणनीति का हिस्सा बताती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएस प्रारंभिक परीक्षा)

बहुविकल्पीय प्रश्न 1: राजस्थान विधानसभा में युवा मामले एवं खेल विभाग (मांग संख्या 26) पर ध्वनिमत से स्वीकृत अनुदान मांगें कितनी थीं?

- (क) ₹2,298,528,000
- (ख) ₹1,000,000,000
- (ग) ₹7,200,000,000
- (घ) ₹229,852,800,000

उत्तर: (क)

व्याख्या: ध्वनिमत से स्वीकृत अनुदान मांगें ₹2,298,528,000 थीं, जो ₹229.8528 करोड़ के बराबर है। अन्य विकल्पों में या तो शून्य का स्थान गलत है या फिर चर्चा में बताए गए वास्तविक आंकड़े से मेल नहीं बैठता।

बहुविकल्पीय प्रश्न 2: विधानसभा में प्रस्तुत तुलना के अनुसार कौन-सा युग्म सही है?

- (क) पूर्ववर्ती सरकार (5 वर्ष) क्रम से हटकर नियुक्तियाँ: 186; वर्तमान सरकार (2 वर्ष): 248
- (ख) पूर्ववर्ती सरकार (5 वर्ष) खिलाड़ी सहायता: ₹40 करोड़; वर्तमान सरकार (2 वर्ष): ₹72 करोड़
- (ग) पूर्ववर्ती सरकार (5 वर्ष) क्रम से हटकर नियुक्तियाँ: 248; वर्तमान सरकार (2 वर्ष): 186
- (घ) "खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल-2025" पूर्ववर्ती सरकार ने आयोजित किया; वर्तमान सरकार ने कोई आयोजन नहीं किया

उत्तर: (ग)

व्याख्या: प्रस्तुत तुलना में पूर्ववर्ती सरकार के पाँच वर्षों में 248 क्रम से हटकर नियुक्तियाँ और वर्तमान सरकार के दो वर्षों में 186 क्रम से हटकर नियुक्तियाँ बताई गईं। बाकी विकल्प या तो आँकड़ों को उलट देते हैं या आयोजन/नीति दावों के विपरीत हैं।

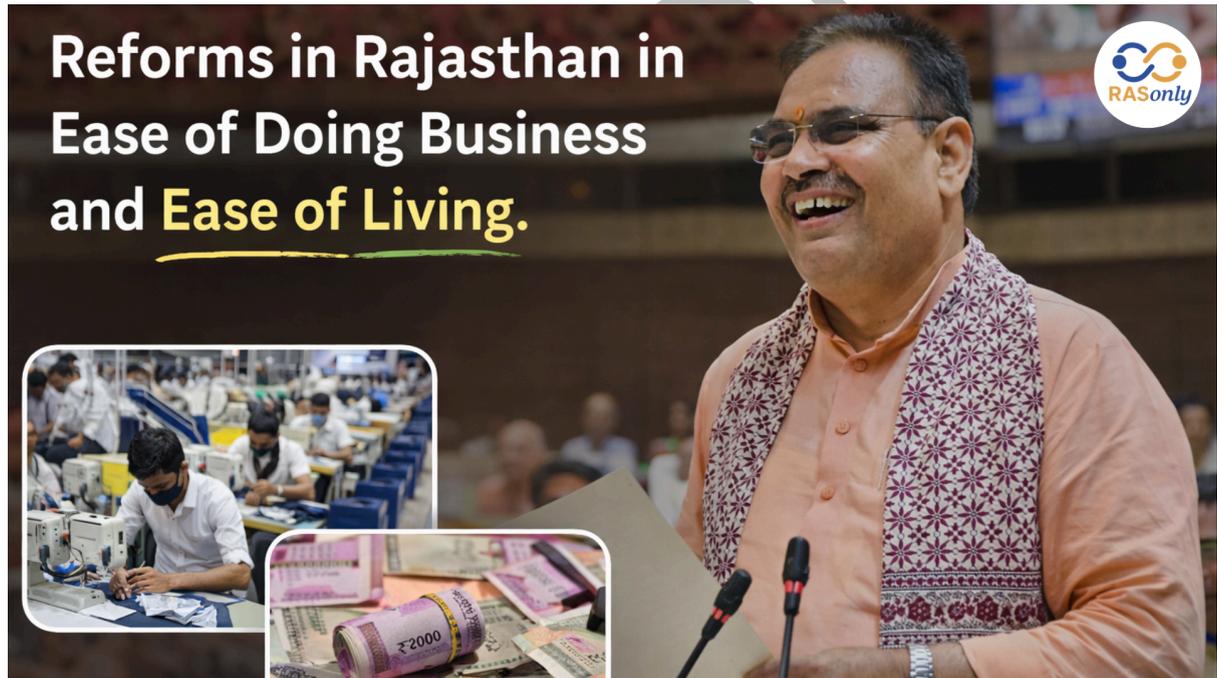
बहुविकल्पीय प्रश्न 3: मंत्री के अनुसार खेल परिणाम और कल्याणकारी उपायों के बारे में कौन-सा कथन सही है?

- (क) राजस्थान ने "खेलो इंडिया युवा खेल" में 34 पदक जीते और ₹10 लाख बीमा कवरेज लागू किया
- (ख) राजस्थान ने "खेलो इंडिया युवा खेल" में 60 पदकों के साथ तीसरा स्थान पाया और ₹25 लाख तक बीमा कवरेज देता है
- (ग) राजस्थान ने "खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल-2024" में 3,400 खिलाड़ियों के साथ आयोजन किया और ₹50 लाख बीमा कवरेज दिया
- (घ) राजस्थान ने "खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल-2025" में 60 पदक जीते और बीमा कवरेज केवल प्रशिक्षकों को मिलता है

उत्तर: (ख)

व्याख्या: मंत्री ने कहा कि “खेलो इंडिया युवा खेल” में राजस्थान ने 60 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया और “खेल जीवन बीमा योजना” के तहत खिलाड़ियों को अधिकतम ₹25 लाख तक दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जा रहा है। अन्य विकल्प आयोजनों, पदकों और कवरेज सीमा को गलत तरीके से जोड़ते हैं।

Reforms in Rajasthan in Ease of Doing Business and Ease of Living.



The government of Rajasthan through Chief Minister Bhajanlal Sharma has made a significant move towards bettering Ease of Doing Business and Ease of Living by scaling off unnecessary compliances and regulations in a gradual manner. The areas that are covered under the reform agenda include land use, building and construction, labour, business licensing and public utilities. An action plan is developed and well structured with the assistance of Chief Secretary V. Srinivas. The strategy will help minimise procedure delays, streamline approvals, and enhance

facilitation of investors by making amendments to the system level in the form of rationalisation of land-use processes, updating the building by-laws, single-point clearance, and enhancing the single-window system.

Key Reform Measures

Land use and conversion

- The government will consider the system applied in Andhra Pradesh to eliminate land-conversion requirement in some categories and to minimize the delays in the procedure.
- Until definitive lists of prohibition are agreed, the development of mixed land-use can be authorized on the basis of the principle of the permission of all activities with the assistance of the necessary alteration of the building by-laws and the master plan.
- Zone-wise prohibition lists will be spelt out in order to be more predictable.

Industrial agglomeration and infrastructure.

- There will be measures to ensure that there is appropriate utilisation of the unutilised land in industrial cluster.
- Land-allotment policy in the industrial areas will be liberalized.
- Cheap accommodation among industrial workers will be encouraged.
- Public-Private Partnership (PPP): It will be encouraged when it comes to core infrastructure including waste treatment and fire safety.

Constructing by-laws and fire safety.

- There will be rationalization of the height restrictions and setback provisions.
- By-laws and fire safety regulations will also be revised to meet fire safety international best practices.

One-Point Clearance and Simplification of licensing.

Single contact points of nodal agencies.

The government is thinking to use nodal agencies as contact points on:

- No Objection Certificates in building and construction,
- approvals associated with clusters of industries,
- Licences related to health department.
- There will be a working group of studying models used by other states.

cancelation of duplicated licences.

- To avoid having to have several licences in the same compliance, a systematic listing of the business licences will be conducted.

- A working group headed by the Additional Chief Secretary (Industries) will consist of the energy, urban development, local self government, labour, and pollution control board departments.

Shops reform, Utilities reform, compliance reform, low risk, low-stake, minimum regulation.

Commercial outlets and stores.

- The government is contemplating the lifetime registration by making information-based deemed licensing.
- There is also a consideration to allow 24×7 operations of such establishments.

Weights and measures

- Simplification of licence is being ready to enable manufacturers and dealers to get approvals in self-declaration without government inspection.

Electricity connections

- With low-risk groups, mandatory field inspection can be eliminated and be supplied with electricity connections by distribution companies on self-declaration.

The process of digital governance and investment facilitation is supported by the policy of Open Investment Environment.

- Preparative sectors will be determined to fasten investment in the industry.
- The single-window system will be reinforced to minimise the actual time that is spent in project start.
- A state-wide central database of all testing centers (public and private) will be established where MSMEs will be registered.
- A digital repository of state laws, rules, regulations and government orders in sector-wise will be developed at the level of the Law Department.

Legislative Follow-Through

- A Bill will be prepared on the basis of suggestions received during the action plan and draft received by the Government of India and put to the vote to make the compliance and regulatory changes go smoothly and at the same time.
- The government observed that last year it introduced the “Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) to enhance the regulation based on justice and trust rather than punitive measures.
- The government has indicated in the State Budget 2026-27 that it plans to reform its system next generation by introducing a next-generation reform

called **Rajasthan Jan Vishwas Act 2.0** in a bid to enhance good governance and citizen involvement.

Conclusion

The action plan of Rajasthan aims at expedited approvals, lesser duplications of licences, greater single-window facilitation, and increased use of self-statement concerning low risks compliance. Through a mix of regulatory simplification and digital governance and a pre-determined legislative support, the state is making Ease of Doing Business and Ease of Living a governance priority that has direct implications on investment, support of MSMEs, and services to citizens.

MCQs (RAS Prelims)

MCQ 1: What group of sectors would be specifically included in the phased compliance and regulatory simplification action plan of Rajasthan?

- (a) Public utilities, business licensing, and land use, building and construction, and labour.
- (b) Defence procurement, telecom spectrum and space policy.
- (c) Monitoring of banks, monetary policy and supervision of stock markets.
- (d) Sea transport, fisheries export and ocean management.

Answer: (a)

Explanation: The action plan aims at streamlining regulations and procedures in land use, building and construction, labour, business licensing and public utilities to enhance Ease of Doing Business and Ease of Living.

MCQ 2: How is the mixed land-use development facilitation to be achieved pending prohibited lists?

- (a) Moratorium on mixed land-use activity.
- (b) Permission of all activities, which is supported by the modifications in building by-laws and the master plan.
- (c) Compulsory land swap of all categories.
- (d) (Each project) only to be approved by courts.

Answer: (b)

Explanation: The plan takes into account the possibility of mixed land-use development based on the allowance of activities by default, and the amendments to

the building by-laws and the master plan are required, prohibited lists are being determined.

MCQ 3: Which of the following is suggested to enable other governance to have quicker approvals and improved clarity on compliance?

- (a) A nationwide prohibition on PPP in the industrial infrastructure.
- (b) A centralised online database of state laws, rules, regulations, and government orders by the sector.
- (c) substitution of the single- window system with the multi-agency consecutive approvals.
- (d) Limit MSME testing of the facilities to government labs.

Answer: (b)

Explanation: It is proposed to establish a single centralised digital repository on the level of the Law Department, as well as enhance the single-window system and develop a single database consisting of the MSME testing facilities.

राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग से जुड़े सुधार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए अनावश्यक अनुपालन और विनियमों को चरणबद्ध रूप से कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुधार एजेंडे में भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण, श्रम, व्यवसाय लाइसेंसिंग और जन उपयोगिताएं शामिल हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के मार्गदर्शन में एक सुव्यवस्थित कार्य-योजना तैयार की गई है। इस रणनीति का उद्देश्य प्रक्रियागत देरी घटाना, अनुमोदनों को सरल बनाना और निवेशक सुविधा को मजबूत करना है। इसके लिए भूमि-उपयोग प्रक्रियाओं का तर्कसंगतकरण, भवन उपविधियों का अद्यतन, एकल बिंदु स्वीकृतियां तथा एकल खिड़की प्रणाली को सुदृढ़ करने जैसे प्रणालीगत सुधार प्रस्तावित हैं।

प्रमुख सुधार उपाय

भूमि उपयोग और भूमि-रूपांतरण

- सरकार कुछ श्रेणियों में भूमि-रूपांतरण की आवश्यकता समाप्त करने और प्रक्रियागत देरी घटाने के लिए आंध्र प्रदेश में लागू प्रणाली पर विचार करेगी।

- निषिद्ध सूचियां अंतिम रूप से तय होने तक “सभी गतिविधियों की अनुमति” के सिद्धांत पर मिश्रित भूमि-उपयोग विकास को सक्षम बनाने हेतु भवन उपविधियों और मास्टर प्लान में आवश्यक संशोधनों पर विचार किया जाएगा।
- अधिक पूर्वानुमेयता के लिए जोन-वार निषिद्ध सूचियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएंगी।

औद्योगिक क्लस्टर और आधारभूत ढांचा

- औद्योगिक क्लस्टरों में खाली/अप्रयुक्त भूमि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे।
- औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन नीति को अधिक उदार बनाया जाएगा।
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए सस्ता आवास उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- अपशिष्ट उपचार और अग्नि सुरक्षा जैसी आधारभूत व्यवस्थाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

भवन उपविधियां और अग्नि सुरक्षा

- ऊंचाई संबंधी प्रतिबंधों और सेटबैक प्रावधानों का तर्कसंगतकरण किया जाएगा।
- भवन उपविधियों और अग्नि सुरक्षा नियमों को अग्नि सुरक्षा की वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा।

एकल बिंदु स्वीकृति और लाइसेंसिंग का सरलीकरण

नोडल एजेंसियों को एकल संपर्क बिंदु बनाना

- सरकार निम्न कार्यों के लिए नोडल एजेंसियों को एकल संपर्क बिंदु बनाने पर विचार कर रही है:
 - भवन एवं निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र
 - औद्योगिक क्लस्टरों से जुड़े अनुमोदन
 - स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लाइसेंस
- अन्य राज्यों में लागू मॉडलों के अध्ययन के लिए कार्यदल गठित किया जाएगा।

दोहरे लाइसेंस समाप्त करना

- एक ही अनुपालन के लिए कई लाइसेंसों की आवश्यकता समाप्त करने हेतु व्यवसाय लाइसेंसों की व्यवस्थित सूचीकरण प्रक्रिया की जाएगी।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में ऊर्जा, नगरीय विकास, स्थानीय स्वशासन, श्रम तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि विभागों को शामिल कर कार्यदल बनाया जाएगा।

दुकानों, जन उपयोगिताओं और कम जोखिम अनुपालन से जुड़े सुधार

दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

- सूचना-आधारित “स्वीकृत मानी जाने वाली” लाइसेंसिंग के जरिए आजीवन पंजीकरण पर सरकार विचार कर रही है।
- ऐसे प्रतिष्ठानों को 24x7 संचालन की अनुमति देने पर भी विचार किया जा रहा है।

तौल और माप

- लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी है, ताकि निर्माता और विक्रेता बिना सरकारी निरीक्षण के स्व-घोषणा के आधार पर अनुमोदन प्राप्त कर सकें।

बिजली कनेक्शन

- कम जोखिम श्रेणियों में फील्ड निरीक्षण की अनिवार्यता हटाने पर विचार है और स्व-घोषणा के आधार पर वितरण कंपनियों द्वारा बिजली कनेक्शन जारी किए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है।

डिजिटल शासन और निवेश सुविधा

- औद्योगिक निवेश को तेज करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।
- परियोजनाओं की शुरुआत में लगने वाला वास्तविक समय कम करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली को अधिक मजबूत किया जाएगा।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सभी परीक्षण सुविधाओं का राज्य-स्तरीय एकीकृत डेटाबेस बनाया जाएगा।
- विधि विभाग स्तर पर क्षेत्रवार राज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और सरकारी आदेशों का केंद्रीकृत डिजिटल भंडार विकसित किया जाएगा।

विधायी क्रियान्वयन

- अनुपालन और विनियामक बदलावों को एक साथ और सहज रूप से लागू करने के लिए कार्य-योजना के सुझावों तथा भारत सरकार से प्राप्त प्रारूप के आधार पर एक विधेयक तैयार कर स्वीकृति हेतु रखा जाएगा।
- सरकार ने बताया कि पिछले वर्ष दंडात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर न्याय और विश्वास आधारित विनियमन को बढ़ावा देने के लिए “राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन)” लाया गया था।
- राज्य बजट 2026-27 में “राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0” लाने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य सुशासन और नागरिक सहभागिता बढ़ाना है।

निष्कर्ष

राजस्थान की यह कार्य-योजना त्वरित स्वीकृतियों, लाइसेंसों की पुनरावृत्ति घटाने, एकल खिड़की सुविधा को सुदृढ़ करने और कम जोखिम वाले अनुपालनों में स्व-घोषणा के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। विनियामक सरलीकरण, डिजिटल शासन और प्रस्तावित विधायी समर्थन के संयोजन के

जरिए राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को शासन की प्राथमिकता बना रहा है, जिसका सीधा प्रभाव निवेश, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों के समर्थन और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आर ए एस)

बहुविकल्पीय प्रश्न 1: राजस्थान की चरणबद्ध अनुपालन और विनियामक सरलीकरण कार्य-योजना में कौन-से क्षेत्रों को विशेष रूप से शामिल किया गया है?

- (क) जन उपयोगिताएं, व्यवसाय लाइसेंसिंग, भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण, तथा श्रम
 - (ख) रक्षा खरीद, दूरसंचार स्पेक्ट्रम और अंतरिक्ष नीति
 - (ग) बैंक निगरानी, मौद्रिक नीति और शेयर बाजार पर्यवेक्षण
 - (घ) समुद्री परिवहन, मत्स्य निर्यात और महासागर प्रबंधन
- उत्तर: (क)

व्याख्या: कार्य-योजना का उद्देश्य भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण, श्रम, व्यवसाय लाइसेंसिंग और जन उपयोगिताओं में नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना है, ताकि व्यापार करने में सुगमता और जीवन-यापन में सुगमता में सुधार हो सके।

बहुविकल्पीय प्रश्न 2: निषिद्ध सूचियां तय होने तक मिश्रित भूमि-उपयोग विकास को कैसे सक्षम बनाने पर विचार किया गया है?

- (क) मिश्रित भूमि-उपयोग गतिविधि पर पूर्ण रोक
 - (ख) भवन उपविधियों और मास्टर प्लान में संशोधन के साथ "सभी गतिविधियों की अनुमति" का सिद्धांत
 - (ग) सभी श्रेणियों में अनिवार्य भूमि अदला-बदली
 - (घ) प्रत्येक परियोजना को केवल न्यायालयों से अनुमोदित कराना
- उत्तर: (ख)

व्याख्या: प्रस्तावित योजना में निषिद्ध सूचियां अंतिम रूप से तय होने तक "सभी गतिविधियों की अनुमति" के सिद्धांत पर मिश्रित भूमि-उपयोग विकास को सक्षम बनाने की बात है, जिसके लिए भवन उपविधियों और मास्टर प्लान में आवश्यक संशोधन किए जाने पर विचार किया गया है।

बहुविकल्पीय प्रश्न 3: तेज स्वीकृतियों और अनुपालन स्पष्टता के लिए कौन-सा उपाय प्रस्तावित है?

- (क) औद्योगिक आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर देशव्यापी प्रतिबंध
 - (ख) विधि विभाग स्तर पर क्षेत्रवार राज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और सरकारी आदेशों का केंद्रीकृत डिजिटल भंडार
 - (ग) एकल खिड़की प्रणाली को हटाकर बहु-एजेंसी क्रमिक अनुमोदन लागू करना
 - (घ) सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों की परीक्षण सुविधाओं को केवल सरकारी प्रयोगशालाओं तक सीमित करना
- उत्तर: (ख)

व्याख्या: कार्य-योजना में विधि विभाग स्तर पर एक केंद्रीकृत डिजिटल भंडार बनाने का प्रस्ताव है, साथ ही एकल खिड़की प्रणाली को सुदृढ़ करने और सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों की सभी परीक्षण सुविधाओं का राज्य-स्तरीय डेटाबेस बनाने की बात भी कही गई है।

RASonly